Medical facilities for retired Commissioned Officers of N.C.C.

4932. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what sort of medical facilities are available to released Emergency Commissioned Officers who retired after serving in the N.C.C.; and

(b) if no such facilities are available, the steps taken by Government to provide them medical aid from military hospitals or CGHS dispensaries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b) Retired N.C.C. whole time officers, including those released Emergency Commissioned Officers who later joined N.C.C., are not entitled to treatment either from Military hospitals or through C.G.H.S. However, they can avail of medical facilities in Government Civil hospitals throughout the country like other citizens of India.

Modernisation of armed forces

4933. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in view of our national security requirements, the armed forces ungently require modernisation and re-equipments; and

(b) what steps Government intend to take with regard to the urgently needed modernisation of armed forces since the outlay on defence in the budget remains virtually static ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Modernisation of our Armed Forces is an on-going process which takes into account the changing threat scenario, technologies, the geopolitical environment as well as the availability of the resources. A concerted exercise is undertaken each year to determine modernisation priorities. Our Armed Forces are being equipped and modernised to maintain highest level of defence preparedness.

(b) The expenditure on defence during the past few years has not remained static. Every year, a portion of the defence budget is earmarked for undertaking modernisation. It would not be in national interest to divulge the exact details of modernisation programme of our Armed Forces.

Vacant posts of Maulvis in the Army

4934. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of posts advertised during the period 1992-93 and 1993-94 for 'MAULVIS' in the Army; and

(b) what is the number of vacant posts as on the 31st March, 1994 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) During the year 1992-93 four posts and during 1993-94 two posts of 'MAULVIS' in the Army were advertised;

(b) As on 31st March, 1994, three posts of 'MAULVIS' were vacant.

Acquisition of land for firing range in South Bihar

4935. SHRI O. P. KOHLI :

SHRI RAM JETHMALANI :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether 245 villages in Palamu, Gumla and Ranchi districts of South Bihar have been acquired for the proposed expansion of Netarhat Field Firing Range;

(b) whether more than one lakh tribals of these villages will have to be evicted for this purpose;

(c) whether Government have chalked out plans for proper rehabilitation of the tribals before evicting them from their ancestral homes; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

अग्नि का सेना में शामिल किया जाना

4936. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "अग्नि" को शामिल न करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और यदि नहीं तो इसे कब तक शामिल कर लिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : **(क) और (ख)** "अग्नि" एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है । रि-एण्टरी तकनालाजी स्थापित करने के लिए यह एक तकनालाजी प्रदर्शन वाहन है । 19 फरवरी, 1994 को अपने तीसरे उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है ।

इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए राशि

4937. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष के दौरान और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए राज्यवार कुल कितना आबंटन किया गया है ।

(ख) इन आबंटनों में मध्य प्रदेश का जिलावार हिस्सा कितना है :

(ग) चालू वर्ष के दौरान और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में चालू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश हेतु इस क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश के मंजूर किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्ड फलेरियो) : (क) योजना आयोग राज्यों के लिए इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट उप क्षेत्रवार आबंटन नहीं करता है । इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :—

अवधि	परिव्यय
1994-95—140.6	करोड़ रुपए
आठवीं योजना—611	करोड़ रुपए

(ख) इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है । इलेक्ट्रानिकी विभाग अपने स्रोतों को विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर इलेक्ट्रानिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटित करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है ।

(ग) मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि की सहायता से विभिन्न संगठनों/संस्थानों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का सूची विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है

(घ) वर्ष 1993 के दौरान फैक्स कार्डों एवं अन्य संचार वस्तुओं तथा वीडियो टेप कैसटों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीवी) तथा 100% नियार्तोन्मुखी (ईओयू) योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 2 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें 157 लाख रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश शामिल है